भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
20.08.2025 के
अतारांकित प्रश्न सं. 4435 का उत्तर

रेलवे स्टेशनों का उन्नयन

4435. श्री सु. वेंकटेशन:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन प्रमुख रेलवे स्टेशनों के कार्य पूरा होने की अनुमानित तिथि क्या है जिन्हें आधुनिक यात्री सुविधाओं के साथ "विश्वस्तरीय" मानकों के अनुसार उन्नत किया जा रहा है;

(ख) सरकार किस प्रकार यह सुनिश्चित कर रही है कि स्टेशन पुनर्विकास परियोजनाओं में लागत वृद्धि और विलंब से बचा जा सके; और

(ग) क्या सभी बड़ी रेललाइनों के मार्गों के पूर्ण विद्युतीकरण के लिए कोई समय-सीमा नियत है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ग): रेल मंत्रालय ने भारतीय रेल पर स्टेशनों के विकास हेतु 'अमृत भारत स्टेशन योजना' शुरू की है। इस योजना में दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ सतत आधार पर स्टेशनों के विकास की परिकल्पना की गई है।

ग्राहक अनुभव उन्नत करने और बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए, भारतीय रेल ने दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की है।

इस योजना में स्टेशनों के सुधार के लिए मास्टर प्लान तैयार करना और चरणबद्ध तरीके से उनका क्रियान्वयन करना शामिल है। मास्टर प्लानिंग में निम्नलिखित शामिल हैं:

- स्टेशन पहुंच और परिचलन क्षेत्र में सुधार
- शहर के दोनों ओर स्टेशन का एकीकरण
- स्टेशन भवन में सुधार
- प्रतीक्षालय, शौचालय, बैठने की व्यवस्था, वाटर बूथों में सुधार
- यात्री यातायात के अनुरूप चौड़े पैदल पार पथ/एयर कॉन्कोर्स का प्रावधान
- लिफ्ट/एस्केलेटर/रैंप का प्रावधान
- प्लेटफार्म की सतह में सुधार/प्रावधान और प्लेटफार्म पर कवर
- 'एक स्टेशन एक उत्पाद' जैसी योजनाओं के माध्यम से स्थानीय उत्पादों के लिए कियोस्क का प्रावधान
- पार्किंग क्षेत्र, मल्टीमॉडल एकीकरण
- दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं
- बेहतर यात्री सूचना प्रणाली
- प्रत्येक स्टेशन पर आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए एक्जीक्यूटिव लाउंज, व्यावसायिक बैठकों के लिए निर्दिष्ट स्थान, भू-दृश्यांकन आदि का प्रावधान

इस योजना में दीर्घकालिक और पर्यावरण अनुकूल समाधान, आवश्यकतानुसार गिट्टी रहित रेलपथ आदि के लिए चरणबद्ध तरीके से कार्य करना और व्यवहार्यता तथा दीर्घावधि में स्टेशन पर सिटी सेंटर का निर्माण भी शामिल है।

इस योजना के अंतर्गत विकास के लिए अब तक 1337 स्टेशनों की पहचान की गई है। अब तक इस योजना के अंतर्गत चरण-I में 105 स्टेशनों पर कार्य पूरा हो चुका है।

इसके अलावा, रेलवे स्टेशनों का विकास/पुनर्विकास/उन्नयन जटिल प्रकृति का होता है जिसमें यात्रियों और रेलगाड़ियों की संरक्षा शामिल होती है और इसके लिए दमकल विभाग, धरोहर, पेड़ों की कटाई, विमानपत्तन संबंधी स्वीकृति इत्यादि जैसी विभिन्न सांविधिक स्वीकृतियों की आवश्यकता होती है। इनकी प्रगति जनोपयोगी सेवाओं को स्थानांतरित करना, (जिनमें जल/सीवेज लाइन, ऑप्टिकल फाइबर केबल, गैस पाइप लाइन, पावर/सिगनल केबल इत्यादि शामिल हैं) अतिक्रमण, यात्री संचलन को बाधित किए बिना रेलगाड़ियों का परिचालन, रेलपथ एवं उच्च वोल्टेज बिजली लाइनों के निकट सान्निध्य में किए जाने वाले कार्यों के कारण गति प्रतिबंध आदि जैसी ब्राउन फील्ड संबंधी चुनौतियों के कारण भी प्रभावित होती है और ये कारक कार्य के समापन समय को प्रभावित करते हैं। अत:, इस समय कोई समय-सीमा नहीं बताई जा सकती है।

अमृत भारत स्टेशन योजना सहित स्टेशनों के विकास/उन्नयन का वित्तपोषण सामान्यतः योजना शीर्ष-53 'ग्राहक सुविधाएँ' के अंतर्गत किया जाता है। योजना शीर्ष-53 के अंतर्गत आवंटन और व्यय का विवरण क्षेत्रीय रेल-वार रखा जाता है, न कि कार्य-वार, स्टेशन-वार या राज्य-वार। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए योजना शीर्ष-53 के अंतर्गत ₹12,118 करोड़ का आबंटन किया गया है।

भारतीय रेल में परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक सुस्थापित तंत्र है, जिसमें उनकी समीक्षा, निरीक्षण, समय और लागत में वृद्धि की जांच, कार्यों की गुणवत्ता और लेखा परीक्षा शामिल है। परियोजनाओं की विभिन्न स्तरों पर निगरानी की जाती है, जिसमें भारतीय रेल के समर्पित पोर्टल भारतीय रेलवे परियोजना स्वीकृति एवं प्रबंधन (आईआरपीएसएम) के माध्यम से भी निगरानी की जाती है। विभिन्न संहिताओं और नियमावलियों में निर्धारित मानकों और विशिष्टताओं का पालन करते हुए कार्य किए जाते हैं। विभिन्न एजेंसियों/अधिकारियों/बहु-विषयक टीमों द्वारा समय-समय पर निर्धारित निर्देशों के अनुसार निरीक्षण/लेखा परीक्षा/जाँच की जाती है और सुधार हेतु त्वरित कार्रवाई की जाती है।

निष्पादन इकाइयों के सामने आने वाली समस्याओं का तदनुसार समाधान किया जाता है। यह एक सतत और निरंतर प्रकिया है।

<u>विद्युतीकरण</u>

भारतीय रेल पर रेल नेटवर्क का विद्युतीकरण मिशन मोड में शुरू किया गया है। अब तक, लगभग 99% बड़ी लाइन नेटवर्क का विद्युतीकरण हो चुका है। शेष नेटवर्क का विद्युतीकरण शुरू हो चुका है। 2014-25 के दौरान और 2014 से पहले किए गए विद्युतीकरण का विवरण निम्न प्रकार है।

अवधि	**मार्ग किलोमीटर**
से 2014 पहले (वर्ष 60 लगभग)	**21,801**
25-2014	**46,900**

विद्युतीकरण परियोजना/ओं का पूरा होना विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है जैसे वन विभाग के अधिकारियों द्वारा वन मंजूरी, उल्लंघनकारी उपयोगिताओं का स्थानांतरण, विभिन्न प्राधिकरणों से वैधानिक मंजूरी, क्षेत्र की भूवैज्ञानिक और स्थलाकृतिक स्थितियां, परियोजना/ओं स्थल क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति, जलवायु परिस्थितियों के कारण विशेष परियोजना के लिए एक वर्ष में कार्य महीनों की संख्या आदि। ये सभी कारक परियोजना/ओं के पूरा होने के समय को प्रभावित करते हैं।

****